पीथमपुर मध्यप्रदेश का इंडस्ट्रियल ग्रोथ इंजन

नवभारत न्यूज़

इंदौर/पीथमपुर/धार, 8 जुलाई. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बुधवार को पीथमपुर स्थित लिउगोंग इंडिया के नए मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का उद्घाटन किया. कंपनी ने अपनी मौजूदा इकाई के विस्तार पर 272 करोड़ रुपये का अतिरिक्त निवेश किया है.

इस विस्तार से कंपनी की वार्षिक उत्पादन क्षमता ×,250 से बढ़कर 7,500 मशीनें हो जाएगी और प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से 5,000 से अधिक रोजगार के अवसर सृजित होंगे. मुख्यमंत्री ने कहा कि पीथमपुर मध्यप्रदेश की औद्योगिक अर्थव्यवस्था का ग्रोथ इंजन है और यहां %मेक इन इंडिया-मेक इन एमपी% का मजबूत इकोसिस्टम विकसित किया जा रहा है. प्रदेश सरकार ग्रीन इंडस्ट्री, इलेक्ट्रिक व्हीकल, एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग और निर्यात आधारित उद्योगों को बढ़ावा दे रही है. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में रा'य सरकार निवेश और औद्योगिक विकास के सभी लक्ष्य तय समय में हासिल करेगी. डॉ. यादव ने बताया कि पिछले दो वर्षों में प्रदेश में लगभग 10 हजार करोड़ रुपये का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई आया है, जबकि वर्ष 2026 के पहले छह माह में 76,862 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं. उन्होंने कहा कि नई औद्योगिक इकाइयों से प्रदेश में बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं.

एमपी पर लगातार बढ़ रहा निवेशकों का भरोसा

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि यह केवल अनाउंसमेंट करने वाली नहीं, धरातल पर डेवलपमेंट लाने वाली सरकार है. उन्होंने कहा कि पीथमपुर मध्यप्रदेश का ही नहीं, पूरे देश का 'मैन्युफैक्चरिंग गेटवे' बन चुका है. एक माह के भीतर यहां दूसरी बड़ी वैश्विक कंपनी द्वारा नई औद्योगिक इकाई की स्थापना इस बात का प्रमाण है कि निवेशकों का भरोसा मध्यप्रदेश पर लगातार बढ़ रहा है.

दुनिया की प्रमुख हैवी अर्थ मूवर्स निर्माता कंपनियों में शामिल लिउगोंग की नई इकाई से स्थानीय एमएसएमई और ऑटो कंपोनेंट उद्योगों को भी मजबूती मिलेगी. कार्यक्रम में कंपनी के ग्लोबल वाइस प्रेसिडेंट ल्यो ग्योबिंग, कंट्री हेड वरुण विजयवर्गीय सहित जनप्रतिनिधि और उद्योग जगत के प्रतिनिधि मौजूद रहे.

दुग्ध समृद्धि संपर्क अभियान 13 जुलाइ से होगा शुरू

प्रशासनिक संवाददाता

भोपाल, 8 जुलाई. प्रदेश में दुग्ध उत्पादन बढ़ाने, किसानों, पशुपालकों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और विभाग द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी प्रत्येक पशुपालक तक आसानी से पहुंचे, इस उद्देश्य से बुधवार को पशुपालन एवं डेयरी विभाग के प्रमुख सचिव उमाकांत उमराव ने संचालनालय पशुपालन एवं डेयरी सभागार में किसानों के प्रतिनिधि मंडल के साथ बैठक की.

विभाग द्वारा संचालित योजनाओं और दुग्ध उत्पादन को बढ़ाने की दिशा में किए जा रहे कार्यों पर विस्तार से चर्चा की .साथ ही उनके सुझाव भी प्राप्त किए. बैठक में प्रमुख सचिव उमराव ने किसान संघ के पदाधिकारियों को प्रदेश में पशुपालन को बढ़ावा देने, प्रदेश को दूध की राजधानी बनाने और दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा किए जा रहे कार्यों की जानकारी दी. उन्होंने कहा कि पशुओं के नस्ल सुधार, पशु पोषण, टीकाकरण एवं सेक्स सॉर्टेड सीमेन के बारे में जानकारी देने के लिए प्रदेश में दुग्ध समृद्धि संपर्क अभियान चलाया जा रहा है. अभियान के दो चरण पूरे हो गए है. तीसरा चरण 13 जुलाई से शुरू होगा.

नए शिक्षकों की ज्वाइनिंग प्रक्रिया शुरू

15 तक शिक्षकों को पदभार ग्रहण करने के निर्देश

नवभारत प्रतिनिधि

भोपाल, 8 जुलाई. प्रदेश के सरकारी स्कूलों में नए नियुक्त होने वाले शिक्षकों की नियुक्ति शुरू हो चुकी है. ता दें लोक शिक्षण संचालनालय ने 2025-26 के तहत चयनित माध्यमिक और प्राथमिक शिक्षकों के नियोजन की प्रक्रिया को तेजी से पूरा करने के निर्देश दिए हैं.

विभाग ने प्रदेश के सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को पत्र जारी कर कहा है कि नवनियुक्त शिक्षकों को 7 जुलाई से 15 जुलाई के बीच हर हाल में पदभार ग्रहण कराना सुनिश्चित किया जाए. जारी निर्देशों के अनुसार सभी नियुक्त अभ्यर्थियों को सबसे पहले जिला शिक्षा अधिकारी की स्थिति में विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में उपस्थित होना होगा. वहां नियुक्ति आदेश में उल्लेखित सभी मूल दस्तावेजों का मिलान और सत्यापन किया जाएगा. इसके साथ ही अभ्यर्थियों को आवश्यक छायाप्रतियां और जरूरी शपथ पत्र भी प्रस्तुत करने होंगे. वहीं विभाग ने इस बार सुरक्षा और प्रामाणिकता के कड़े इंतजाम किए हैं, जिसके तहत अभ्यर्थियों के आधार कार्ड से उनकी सही पहचान सुनिश्चित करने के बाद ही दस्तावेजों का मिलान किया जाएगा.

यदि किसी भी दस्तावेज में कोई संदेह या विसंगति पाई जाती है, तो पदभार ग्रहण नहीं कराया जाएगा. इसके अलावा खेल, संगीत, गायन-वादन और नृत्य विषयों के शिक्षकों की डिग्रियों की जांच के लिए विशेष नियम बनाए गए हैं. विभाग ने स्पष्ट किया है कि केवल मान्यता प्राप्त संस्थाओं की अंकसूची या प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे. प्रयाग संगीत समिति इलाहाबाद प्राचीन कला केन्द्र चण्डीगढ़ और अखिल भारतीय गंधर्व महाविद्यालय मुम्बई को यूजीसी से मान्यता प्राप्त नहीं होने के कारण इनकी अंकसूचियों को सीधे तौर पर अमान्य किया गया है.

सड़क निर्माण की मांग को लेकर ग्रामीण ने शुरू की दंडवत यात्रा

मुरैना. जिले की दिमनी विधानसभा क्षेत्र के ग्राम जोहां हवेली निवासी एक युवक ने जोहां-श्यामपुर मार्ग के निर्माण की मांग को लेकर अन्न-जल त्यागते हुए सांसद कार्यालय तक दंडवत यात्रा शुरू की है. ग्रामीण नवनीत सिंह तोमर ने बुधवार को मुरैना जिला मुख्यालय स्थित सांसद शिवमंगल सिंह तोमर के कार्यालय तक लगभग 30 किलोमीटर लंबी दंडवत यात्रा शुरू की. उनका कहना है कि सड़क निर्माण की दिशा में ठोस पहल होने तक उनका आंदोलन जारी रहेगा. नवनीत सिंह तोमर ने बताया कि जोहां-श्यामपुर मार्ग लंबे समय से जर्जर स्थिति में है. बरसात के दौरान सड़क कीचड़ और गड्ढों में तब्दील हो जाती है.

1 करोड़ नागरिकों तक पहुंचा साइबर सुरक्षा का संदेश

विशेष संवाददाता

भोपाल, 8 जुलाई. मध्यप्रदेश पुलिस का 15 दिवसीय प्रदेशव्यापी 'सेफ क्लिक 2.0' साइबर सुरक्षा जनजागरूकता अभियान बुधवार को संपन्न हो गया.

पुलिस का दावा है कि अभियान के दौरान एक करोड़ से अधिक नागरिकों तक प्रत्यक्ष रूप से साइबर सुरक्षा का संदेश पहुंचाया गया, जबकि डिजिटल एवं सोशल मीडिया के माध्यम से छह करोड़ से अधिक लोगों तक इसकी पहुंच बनाई गई. भोपाल स्थित नरोनहा प्रशासन अकादमी के स्वर्ण जयंती सभागार में आयोजित समापन समारोह में पुलिस महानिदेशक कैलाश मकवाणा ने कहा कि आने वाले वर्षों में साइबर अपराध कानून-व्यवस्था के सामने सबसे बड़ी चुनौतियों में शामिल होंगे. ऐसे में जनजागरूकता ही नागरिकों की सबसे मजबूत सुरक्षा है. उन्होंने कहा कि 'सेफ क्लिक 1.0' की सफलता के बाद डिजिटल अरेस्ट जैसे साइबर अपराधों में कमी आई है.

मध्यप्रदेश में अगले 4 दिन तेज बारिश का अलर्ट

24 घंटे में 4 से 8 इंच तक बारिश होने की संभावना

अति भारी वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी

भोपाल, 8 जुलाई. मध्यप्रदेश में मानसून पूरी तरह सक्रिय है और प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में लगातार तेज बारिश हो रही है. मौसम विभाग ने अगले चार दिनों तक भारी से अति भारी वर्षा की चेतावनी जारी की है. इस दौरान कई क्षेत्रों में 24 घंटे में 4 से 8 इंच तक बारिश होने की संभावना है.

बुधवार के लिए श्योपुर, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, सागर और टीकमगढ़ में अति भारी वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जबकि ग्वालियर, मुरैना, दतिया, कटनी, जबलपुर, रायसेन, नर्मदापुरम, इंदौर, धार, झाबुआ और अन्य जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है.

लगातार हो रही बारिश से पन्ना, छतरपुर और खंडवा सहित कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं. खजुराहो क्षेत्र में कई संपर्क मार्ग बंद हो गए हैं और नदियों के जलस्तर में वृद्धि से जनजीवन प्रभावित हुआ है. मंगलवार को प्रदेश के 29 जिलों में वर्षा दर्ज की गई, जिनमें खजुराहो में सबसे अधिक लगभग पौने दो इंच बारिश हुई. वर्षा के कारण प्रदेशभर में तापमान में भी गिरावट आई है. इंदौर, भोपाल, जबलपुर और उज्जैन समेत प्रमुख शहरों में अधिकतम तापमान सामान्य से नीचे दर्ज किया गया.

मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में अब तक 200 .5 मिमी, यानी लगभग 8 इंच वर्षा हो चुकी है, जो सामान्य से करीब 5 प्रतिशत अधिक है. पश्चिमी मध्य प्रदेश में सामान्य से 21 प्रतिशत अधिक बारिश हुई है, जबकि पूर्वी हिस्से में वर्षा अभी भी सामान्य से कम है. देवास जिले में इस सीजन की सर्वाधिक, लगभग 16 इंच वर्षा दर्ज की गई है. मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि जुलाई मानसून का सबसे सक्रिय महीना होता है, इसलिए आने वाले दिनों में भी तेज बारिश का सिलसिला जारी रहने की संभावना है.

चेतावनी : फर्जी रेलवे भर्ती विज्ञापनों से सावधान रहें

भोपाल, 8 जुलाई. पश्चिम मध्य रेलवे के भोपाल मंडल ने सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहे फर्जी रेलवे भर्ती विज्ञापनों से सतर्क रहने की अपील की है. मंडल के अनुसार कुछ असामाजिक तत्व रेलवे में नौकरी दिलाने के नाम पर युवाओं से ठगी का प्रयास कर रहे हैं.

मंडल रेल प्रबंधक पंकज त्यागी के मार्गदर्शन में जारी चेतावनी में स्पष्ट किया गया है कि भारतीय रेलवे में सभी भर्तियां केवल रेलवे भर्ती बोर्ड (आरआरबी) और रेलवे भर्ती सेल के माध्यम से निर्धारित नियमों एवं पूर्ण पारदर्शिता के साथ की जाती हैं. रेलवे में बिना परीक्षा भर्ती, डायरेक्ट जॉइनिंग या निजी एजेंसियों के माध्यम से चयन की कोई व्यवस्था नहीं है. रेल प्रशासन ने कहा कि 'तुरंत नियुक्ति', 'निश्चित चयन' अथवा 'सीमित योग्यता पर सरकारी नौकरी' जैसे दावे पूरी तरह भ्रामक हैं.

पुणे-दानापुर ट्रेन की अवधि बढ़ी

भोपाल. यात्रियों की बढ़ती मांग को देखते हुए रेलवे प्रशासन ने गाड़ी संख्या 01449/ 01450 पुणे-दानापुर-पुणे दैनिक स्पेशल ट्रेन का संचालन 30 सितंबर तक बढ़ाने का निर्णय लिया है. भोपाल के इटारसी स्टेशन सहित मार्ग के यात्रियों को बड़ी सुविधा मिलेगी. 18 कोचों वाली इस स्पेशल ट्रेन में वातानुकूलित, शयनयान और सामान्य श्रेणी के डिब्बे शामिल हैं. पुणे-दानापुर स्पेशल 16 जुलाई से 28 सितंबर तक तथा दानापुर-पुणे स्पेशल 18 से 30 सितंबर तक प्रतिदिन संचालित होगी. दोनों दिशाओं में ट्रेन इटारसी, जबलपुर, कटनी और सतना सहित प्रमुख स्टेशनों पर ठहराव लेगी.

नर्मदा जल समझौता : श्वेत पत्र करे जारी

विशेष संवाददाता

भोपाल, 8 जुलाई. अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव कुणाल चौधरी ने बुधवार को नर्मदा नदी से जुड़े जल अधिकारों के मुद्दे पर राज्य सरकार पर मध्य प्रदेश के हितों से समझौता करने का आरोप लगाते हुए नर्मदा जल बंटवारे, परियोजनाओं और मुआवजे से जुड़े सभी निर्णयों पर तत्काल श्वेत पत्र जारी करने की मांग की. कुणाल चौधरी ने कहा कि नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण ने मध्य प्रदेश को 18.25 मिलियन एकड़ फीट पानी आवंटित किया था, लेकिन भाजपा सरकार दो दशक से अधिक समय बीत जाने के बाद भी राज्य के हिस्से का पूरा उपयोग नहीं कर सकी है. उनका दावा था कि वर्तमान में केवल लगभग 12 एमएएफ पानी का ही उपयोग हो रहा है, जबकि कई प्रमुख सिंचाई और जल भंडारण परियोजनाएं अधूरी पड़ी हैं या बंद कर दी गई हैं. उन्होंने हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री की अध्यक्षता में हुई अंतरराज्यीय बैठक पर भी सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि राज्य सरकार ने सरकारी भूमि के डूब क्षेत्र के एवज में मिलने वाले 7,669 करोड़ रुपये के मुआवजे का दावा छोड़ दिया.

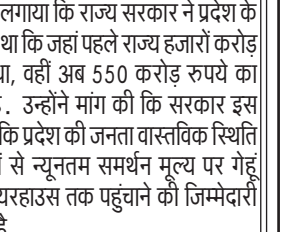

उन्होंने इसे प्रदेश के हितों के साथ विश्वासघात बताया. कुणाल चौधरी ने बरगी डायवर्जन परियोजना में देरी और लागत वृद्धि को प्रशासनिक विफलता तथा भ्रष्टाचार का परिणाम बताते हुए कहा कि सरदार सरोवर परियोजना से प्रभावित हजारों आदिवासी परिवार आज भी समुचित पुनर्वास की प्रतीक्षा कर रहे हैं. उन्होंने सरकार से नर्मदा की लंबित परियोजनाओं, सिंचाई क्षमता, पुनर्वास कार्यों तथा राज्य को आवंटित पूरे जल हिस्से के उपयोग की कार्ययोजना सार्वजनिक करने की मांग की.

प्रदेश में नशे के खिलाफ अभियान तेज

विशेष संवाददाता

भोपाल, 8 जुलाई. मध्यप्रदेश पुलिस मुख्यालय ने मादक पदार्थों के विरुद्ध अभियान को और अधिक प्रभावी बनाने, साइबर अपराधों पर अंकुश लगाने तथा जनशिकायतों के त्वरित एवं गुणवत्तापूर्ण निराकरण के लिए तीन वर्षीय कार्ययोजना तैयार की है.

इसके तहत पुलिस अधिकारियों को समयबद्ध कार्रवाई, तकनीक आधारित पुलिसिंग और समन्वित अभियान चलाने के निर्देश दिए गए हैं. पुलिस महानिदेशक कैलाश मकवाना के निर्देश पर आयोजित रेंज पुलिस महानिरीक्षकों तथा भोपाल एवं इंदौर के अतिरिक्त पुलिस आयुक्तों की बैठक में नशे के खिलाफ कार्रवाई, साइबर सुरक्षा और शिकायत निवारण की प्रगति की समीक्षा की गई. बैठक में निर्णय लिया गया कि 15 जुलाई से शुरू होने वाला राज्यव्यापी जनजागरूकता अभियान 'नशे से दूरी, है जरूरी 2.0' को जन आंदोलन का स्वरूप दिया जाएगा. अभियान में शैक्षणिक संस्थानों, सरकारी विभागों, सामाजिक संगठनों, युवा समूहों तथा धार्मिक संस्थाओं की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी, ताकि युवाओं और आम नागरिकों को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक किया जा सके.

बैठक में संगठित मादक पदार्थ तस्करी नेटवर्क के खिलाफ वित्तीय जांच को मजबूत करने, खुफिया तंत्र को और प्रभावी बनाने तथा पड़ोसी राज्यों के साथ समन्वित कार्रवाई बढ़ाने के निर्देश दिए गए. शैक्षणिक संस्थानों के आसपास ड्रग-फ्री जोन का कड़ाई से पालन कराने और एनडीपीएस अधिनियम से जुड़े मामलों की प्रभावी जांच सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया. साइबर अपराधों की रोकथाम के लिए 25 हजार से अधिक की वित्तीय धोखाधड़ी के मामलों में 72 घंटे के भीतर ई-जीरो एफआईआर दर्ज करने, महिलाओं एवं बच्चों से जुड़े मामलों को प्राथमिकता देने, पीड़ितों की फ्रीज राशि शीघ्र वापस दिलाने के निर्देश दिए.

पेज एक का शेष

बगलामुखी मंदिर के दान में घोटाला

मां बगलामुखी मंदिर पूरी तरह शासन के नियंत्रण में है और इसकी व्यवस्था संभालने के लिए स्थानीय एसडीएम प्रबंध समिति के अध्यक्ष होते हैं. लेकिन इस सरकारी समिति को दरकिनार कर गैर सरकारी निजी समिति द्वारा खुलेआम सोने-चांदी के आभूषण और दान की अवैध वसूली की जा रही थी. कलेक्टर ने बनाई जांच समिति : आगर कलेक्टर प्रीति यादव द्वारा मां बगलामुखी मंदिर में गैर शासकीय समिति द्वारा अवैध वसूली के मामले में एक जांच समिति गठित की है. यह समिति सात दिन के अंदर इस मामले में विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी. इस समिति में जिला पंचायत सीईओ, नलखेड़ा सीएमओ, जिला कोषालय अधिकारी को सदस्य बनाया गया है. जो गैर शासकीय समिति द्वारा की गई अवैध वसूली के मामले में जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी.

कांग्रेस ने गेहूं, मंदिर और नर्मदा मुद्दे...

दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए. नर्मदा जल विवाद समझौते का उल्लेख करते हुए उमंग सिंघार ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार ने प्रदेश के हितों से समझौता किया है। उनका कहना था कि जहां पहले राज्य हजारों करोड़ रुपये के मुआवजे का दावा कर रहा था, वहीं अब 550 करोड़ रुपये का भुगतान करने पर सहमति जताई गई है. उन्होंने मांग की कि सरकार इस समझौते की पूरी शर्तें सार्वजनिक करे ताकि प्रदेश की जनता वास्तविक स्थिति से अवगत हो सके. सरकार किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदती है और उसे सुरक्षित रूप से वेयरहाउस तक पहुंचाने की जिम्मेदारी प्रशासन एवं संबंधित एजेंसियों की होती है.

संकट बढ़ते कर्ज और कथित वित्तीय कुप्रबंधन के कारण प्रदेश पर पांच लाख करोड़ का ऋण हो चुका

कर्ज के बोझ तले दब रही प्रदेश की अर्थव्यवस्था

विशेष संवाददाता

भोपाल, 8 जुलाई. मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने राज्य सरकार पर प्रदेश को गंभीर आर्थिक संकट की ओर धकेलने का आरोप लगाते हुए कहा कि लगातार बढ़ते कर्ज और कथित वित्तीय कु प्रबंधन के कारण प्रदेश पर पांच लाख करोड़ रुपये से अधिक का ऋण हो चुका है.

उन्होंने सरकार से प्रदेश की वास्तविक वित्तीय स्थिति और कर्ज के उपयोग पर श्वेत पत्र जारी करने की मांग की. बुधवार को पत्रकार वार्ता में जीतू पटवारी ने दावा किया कि राज्य सरकार ने हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से सरकारी प्रतिभूतियां जारी कर 3,600 करोड़ रुपये का नया कर्ज लिया है. उनके अनुसार 31 मार्च 2026 तक प्रदेश पर 4,88,714.17 करोड़ रुपये का बकाया ऋण था, जो अब बढ़कर पांच लाख करोड़ रुपये से अधिक हो गया है.

उन्होंने आरोप लगाया कि वित्तीय वर्ष 2026-27 में प्रस्तावित 78,500 करोड़ रुपये के वार्षिक उधार लक्ष्य के मुकाबले सरकार शुरुआती महीनों में ही 12,800 करोड़ रुपये का कर्ज ले चुकी है, जो कुल लक्ष्य का 16 प्रतिशत से अधिक है.

पटवारी ने कहा कि प्रदेश का कुल कर्ज अब वार्षिक बजट से भी अधिक हो गया है, जो सरकार की आर्थिक नीतियों की विफलता का प्रमाण है. उन्होंने आरोप लगाया कि भारी कर्ज लेने के बावजूद किसानों को खाद और सिंचाई जैसी मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, युवाओं के लिए रोजगार के अवसर नहीं बढ़े हैं और शिक्षा व स्वास्थ्य सेवाओं में भी अपेक्षित सुधार नहीं हुआ है.

ब्याज भुगतान में खर्च हो रही राज्य की आय

पटवारी ने यह भी आरोप लगाया कि राज्य की आय का बड़ा हिस्सा विकास कार्यों के बजाय ब्याज भुगतान में खर्च हो रहा है, जिससे आने वाली पीढ़ियों पर आर्थिक बोझ बढ़ेगा. साथ ही उन्होंने कहा कि वित्तीय चुनौतियों के बावजूद सरकार प्रचार-प्रसार और आयोजनों पर फिजूलखर्ची कर रही है तथा भ्रष्टाचार और कमीशनखोरी के कारण सरकारी खजाना कमजोर हुआ है. कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि उनकी पार्टी प्रदेश की आर्थिक स्थिति, सार्वजनिक धन के उपयोग और बढ़ते कर्ज के मुद्दे पर सरकार से लगातार जवाब मांगती रहेगी.

स्वत्वाधिकारी रामगोपाल इन्वेस्टमेंट प्रा. लि. हेतु लेसी एंगेज मीडिया प्रा.लि. के लिए आशीष श्रोती द्वारा 3, इंदिरा प्रेस कॉम्प्लेक्स, रामगोपाल माहेश्वरी मार्ग, महाराणा प्रताप नगर, जोन-1, भोपाल से प्रकाशित एवं नवभारत प्रेस भोपाल प्रा.लि., इंदिरा प्रेस कॉम्प्लेक्स से मुद्रित. संपादक दिलीप झा*, *समाचार चयन के लिए पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत जिम्मेदार, फोन-4939198, ईमेल-bhopalnav@gmail.com RNI Reg. No. 35046/56 डाक पंजीयन क्रमांक M.P/B.P.L/711/2012-14